

दैनिक रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का इमेल आईडी हैक राज्यपाल को भी भेजे गए मेल



नार्वेकर पहले भी रहे हैं सुर्खियों में...

जुलाई 2022 को राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर चुने गए थे. जब उन्होंने कुर्सी संभाली तब उनके सामने एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना था. इस साल उन्होंने एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाकर सुर्खियों में आए गए थे. उन्होंने एकनाथ शिंदे को शिवसेना को ही असली पार्टी का कहा था. उनके इस फैसले से उद्वेग ठाकरे के गुट को बड़ा झटका लगा था. यही नहीं उन्होंने एनसीपी विभाजन मामले में भी महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था. राहुल नार्वेकर ने 2019 में मुंबई के कोलाबा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था. वह पूर्व में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं. नार्वेकर 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे.

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर की मेल आईडी हैक हो गई है. आईडी हैक करने की इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया है कुछ अज्ञात लोगों ने जिनके बारे में पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. यही नहीं हैकिंग के बाद आरोपियों ने राहुल नार्वेकर के मेल आईडी से राज्यपाल रमेश बैस को मेल भी भेज दिया है. राज्यपाल भवन को इसका शक इसलिए हुआ क्योंकि सामान्य तौर पर स्पीकर की तरफ से राज्यपाल को मेल वगैरह जाते रहते हैं जो काम काज से जुड़े होते हैं. पर इस मेल में ऐसा कुछ लिखा था कि राज्यपाल भवन को

शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है. हालांकी जब राज्यपाल ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से संपर्क किया तो स्पीकर ने किसी भी तरह का मेल भेजे जाने से इंकार किया है. दरअसल मेल में कुछ विधायकों की शिकायत की गई थी की उनका व्यवहार सही नहीं है इसलिए उनपर कार्यवाही किया जाना चाहिए. इस मेल को पढ़कर ही राज्यपाल भवन को शक हुआ.

‘बेटी को सीएम बनाना है...’

परिवारवाद का जिक्र कर पवार पर अमित शाह का निशाना

महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है. इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने जलगांव में रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार, उद्वेग ठाकरे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘मैं तो पवार साहब को कहता हूँ कि मोदी साहब को 10 साल हुए, आपको तो 50 साल से महाराष्ट्र की जनता ढो रही है, सहन कर रही है...50 साल तो छोड़िए आप पांच साल का हिसाब दे दीजिए जनता को.’ अमित शाह ने कहा, ‘महाराष्ट्र में तीन पहियों वाली एक ऑटो चलती है, जिसका नाम महाविकास अघाड़ी है.



महाराष्ट्र का विकास कर सकती है.’

इसके तीनों पहिए पंचर हैं. महाराष्ट्र को पंचर वाली ऑटो विकास दे सकती है क्या? एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ही

परिवारवाद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी के सामने जो पार्टियों का गठबंधन बना है वह कौन है? कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी को राहुल गांधी को पीएम बनाना है, उद्वेग ठाकरे को आदित्य ठाकरे को उट बनाना है, शरद पवार को बेटी को सीएम

बनाना है, ममता दीदी को भतीजे को सीएम बनाना है, स्टालिन को बेटे को सीएम बनाना है, इसमें आपके लिए कोई नहीं है. आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी हैं.ह

बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर देशभर में राजनीतिक हलचल का माहौल है. नेताओं द्वारा पाला बदल का सिलसिला भी जारी है. दूसरी ओर वहीं पीएम मोदी द्वारा लालू यादव पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधने और मंच से पूरे देश को अपना परिवार बताने के बाद देशभर में परिवारवाद की राजनीति को लेकर बहस शुरू हो गई है. बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर ‘मोदी का परिवार’ कैपेन चलाया गया जा रहा है. इसमें एक्स अकाउंट पर बीजेपी नेता अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखा है.

पालघर की कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

पालघर : पालघर जिले में एक कंपनी में भीषण आग लग गई है। यह आग तारापुर एमआईडीसी इलाके में लगी है। आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं। आग लगने की वजहों का अभी



तक खुलासा नहीं हो पाया है। लगने का वीडियो सामने आया है। जिसमें आग की ऊंची-ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। दमकल विभाग का कहना

है कि आग लगने की सूचना मिलने के तुरंत बाद गाड़ियों को भेजा गया। कंपनी में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है।

विहार झील के बहाव को मोड़ने का ठेका बीएमसी ने मिशिगन के इंजीनियरों को दिया

मुंबई : बीएमसी ने मिशिगन इंजीनियरों को विहार झील से अतिरिक्त पानी को भांडूप परिसर में निस्पंदन संयंत्र में मोड़ने का प्रोजेक्ट दिया है। 200 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की क्षमता के साथ डिजाइन, निर्माण और संचालन के आधार पर एक पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। हालांकि, परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 59.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 98 करोड़ रुपये (सभी करों सहित) हो गई है। अगर मानसून में मीठी नदी उपत्रन पर होती है तो कुर्ला में क्रांति नगर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और अंधेरी (पूर्व) में साकी नाका जैसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है। कुर्ला और सायन में रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है, जिसके



परिणामस्वरूप स्थानीय सेवाएं बाधित हो गई हैं। 2020 में नियुक्त एक सलाहकार ने सुझाव दिया कि बीएमसी विहार झील से अतिरिक्त पानी को भांडूप संयंत्र की ओर मोड़ दे। यह पानी मानसून के दौरान शहर की दैनिक आपूर्ति में इजाफा करेगा और मीठी से प्रभावित क्षेत्रों को भी राहत देगा। हालांकि, संभावित बोलीदाताओं ने अनुमानित दर से 33% से 48% अधिक बोली लगाई। एक नागरिक अधिकारी ने कहा, ‘परियोजना का अनुमान मार्च 2022 में तैयार किया

गया था और जून 2023 में निविदा आमंत्रित की गई थी। इस अवधि के दौरान, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 7.93% की वृद्धि हुई। साथ ही अनुमानित लागत में 18 फीसदी जीएसटी भी नहीं जोड़ा गया. संशोधित अनुमान के अनुसार, परियोजना की लागत बढ़कर 74.18 करोड़ रुपये हो गई है।’ बीएमसी ने अनुमानित लागत और बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत राशि के बीच अंतर को सत्यापित करने के लिए एक तकनीकी समिति भी नियुक्त की थी। उसके बाद, मिशिगन इंजीनियर्स को एक अनुबंध दिया गया।

सरकार का विकास ही एकमात्र विजन- मुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र का विकास ही उनकी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है. ‘मेरे लिए, ‘सीएम’ का मतलब ‘मुख्यमंत्री’ नहीं है, इसका मतलब ‘आम आदमी’ है। लोगों के लिए काम करते समय, हम केवल आम आदमी का एजेंडा रखते हैं, ‘उन्होंने कहा। ‘हमने मेट्रो कार शोड जैसी उन परियोजनाओं को फिर से शुरू किया है जो एमवीए सरकार के दौरान बंद हो गई थीं। राज्य में तेजी से विकास हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से महाराष्ट्र नंबर वन राज्य है. समृद्धि महामार्ग, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक का निर्माण, 337 किमी मेट्रो लाइन का निर्माण और वसोवा-पालघर तटीय सड़क जैसी परियोजनाओं से लोगों को फायदा होगा। ये परियोजनाएं गेम चेंजर



साबित होंगी, ‘उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने जलयुक्त शिवार और किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता दी है. उन्होंने जोर देकर कहा, एमवीए सरकार ने मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना को रोक दिया था लेकिन हमने इसे फिर से शुरू कर दिया है। अब तक हमने राज्य में 120 जल सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं और 120 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाया गया है। शिंदे ने कहा, ‘पीएम मोदी का विजन है कि

हम जल्द ही 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। उसमें महाराष्ट्र एक ट्रिलियन का योगदान देगा, इसलिए कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के उत्थान के लिए ‘लेक लड़की लखपति’ योजना जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और महिला सम्मान योजना शुरू की है जिसके तहत राज्य सरकार एमएसआरटीसी की सभी श्रेणियों में टिकट किराए में 50% छूट देगी।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

कैफे में आतंकी विस्फोट...

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भारत की ह्रासिलिकॉन वैलीहू है। वहां के लोकप्रिय ह्यारामेश्वरम कैफेहू में बीते शुक्रवार को ऐसा विस्फोट हुआ, जिसकी नीयत और ताकत आतंकी हमले से कम नहीं थी। विस्फोट में 9 लोग घायल हुए। उनमें 45 साल की एक महिला पहचानी गई, जो सेमीकंडक्टर की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में लेखापाल के पद पर कार्यरत है। वह विस्फोट में झुलस गई है और फिलहाल जख्मों से लड़ रही है। शुरूआती जांच के संकेत हैं कि एक अनजान व्यक्ति ने विस्फोट से कुछ मिनट पहले ही उस लोकप्रिय कैफे में बैग रखा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि संदिग्ध की पहचान की जा सके। संभवतः आईईडी विस्फोटक उपकरण उसी बैग में रखा गया था। खान-पान के ऐसे लोकप्रिय स्थलों पर भी सुरक्षा में सुराख देखे गए हैं। वहां पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था नहीं होती। जबकि ऐसे स्थल ही आतंकी या किसी अन्य हमले के ह्यआसान लक्ष्यहू होते हैं। जांच की कुल 8 टीमों का काम कर रही है। पुलिस 2022 से उन आतंकी हमलों के साथ इस विस्फोट के संपर्क की संभावनाओं को भी खंगाल रही है, जहां ऐसे ही विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का आश्वासन दिया है और अपेक्षा की है कि इस घटना का राजनीतिकरण न किया जाए। विपक्षी भाजपा ने इसे कानून-व्यवस्था की नाकामी करार दिया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान-समर्थक नारों से इस विस्फोट को जोड़ा है। सवाल है कि क्या यह माना जाए कि बेंगलुरु में भी पाकिस्तान के दहशतगर्द तत्व और खुफिया एजेंसी आईएसआई पहुंच गए हैं, जिन्होंने ऐसे विस्फोट को अंजाम दिया ? वैसे माहौल को गरम और उग्र बनाने में सत्तारूढ़ कांग्रेस का भी योगदान कम नहीं रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने विस्फोट को 2022 के मंगलूरु विस्फोट से जोड़ दिया, जब राज्य में भाजपा सरकार थी। उपमुख्यमंत्री जैसा जिम्मेदार शख्स यह आरोप किस आधार पर लगा सकता है ? उन्होंने इसके विपरीत ही बयान दिया था और राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया था। ऐसा दोगलापन ही आतंकी घटनाओं का राजनीतिकरण करता है। राज्य और केंद्र सरकार की अपनी-अपनी एजेंसियां हैं, जिनके दायरे परिभाषित हैं। जांच दलों को अपना काम करने दें। वे ही किसी निष्कर्ष की ओर संकेत कर सकते हैं। दरअसल ह्यारामेश्वरम कैफेहू में यह विस्फोट ज्यादा भयावह इसलिए है, क्योंकि यह वहां स्थित है, जहां आईबीएम, एसएपी सरीखी आईटी कंपनियां और कई स्टार्टअप मौजूद हैं। यह देश का प्रौद्योगिकी केंद्र है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पेशेवरों के लिए यह कैफे एक लोकप्रिय ठिकाना है। खान-पान के पकवानों के लिए यह विख्यात है। जब दोपहर एक बजे के करीब विस्फोट हुआ, तो कई पेशेवर वहां लंच कर रहे थे। घायलों में वेल्डर, मैकेनिक, बिजली वाले, मिस्त्री आदि ह्यब्लू कॉलरहू प्रवासी कामगार भी शामिल थे। बेंगलुरु के रेस्टॉरेंट क्षेत्र को अब खुद महसूस करना पड़ेगा कि वे सावधान हो जाएं। अपने ग्राहकों पर निगरानी रखें। एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तैयार करें। उन्हें अपने स्टाफ को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है, ताकि वे किसी भी संदिग्ध व्यवहार वाले व्यक्ति को पहचान सकें। आपात स्थिति के लिए ऐसे मानदंड भी तैयार किए जाएं, ताकि उनका स्टाफ ग्राहकों को बचा कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सके। अस्पताल भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि शहर की होटल एसोसिएशन ने कहा है कि वह सुरक्षा-व्यवस्था को सुधारने के लिए एक योजना तैयार करेगी। होटल वाले अपनी एसोसिएशन के सदस्यों और पुलिस से जल्द ही बैठक कर संवाद करेंगे। जाहिर है कि किसी योजना की रूपरेखा पर भी विमर्श होगा। बेंगलुरु में हमने कई बार सांप्रदायिक दंगों की सूरत भी देखी है।

+91 99877 75650

editor@rookthoklehaninews.com

Faisal Shaikh @faisalrookthok
#faisalrookthok

फडणवीस का पालघर साधु हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान, जल्द ही षड्यंत्र रचने वालों का होगा पदार्पण...

पालघर : पालघर साधु हत्याकांड को लेकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जल्द ही षड्यंत्र रचने वालों का पदार्पण होगा। एक सभा के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं के साथ जो बर्बरता हुई इस प्रकार की घटना मैंने पहले कभी नहीं देखी। हम ये सोचते हैं कि मनुष्यों में इतनी बर्बरता आ कैसे सकती है। वैसे तो इसमें जांच की गई, गिरफ्तारियां भी हुई लेकिन हमारी सत्ता आने के बाद हमने इस मामले में हुए षड्यंत्र के पीछे की जांच करने के लिए केस सीबीआई (CBI) को सौंप दिया है।



क्या हुआ था उस दिन ?

पालघर मांभ लिंगिंग मामला 16 अप्रैल, 2020 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के गडचिंचले गांव में हुई थी। कुछ लोगों ने दो साधुओं और उनके ड्राइवर पर हमला किया और उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। यह घटना कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान इलाके में चोरों के सक्रिय होने की व्हाट्सएप अफवाहों से फैली

थी। कुछ लोगों ने इन तीन यात्रियों को चोर समझ लिया और पत्थरों, कुल्हाड़ियों और लाठियों से उनकी हत्या कर दी। बीच-बचाव करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चार पुलिसकर्मी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे।

यहां बता दें, भारत में व्हाट्सएप पर अफवाहों के कारण हमले और

लिंगिंग की घटनाएं देखी गई हैं, जिनमें अक्सर बच्चों का अपहरण या घूमने वाले डाकू शामिल होते हैं। पालघर में अफवाह फैल गई कि रात में इलाके में अंग निकालने वाले गिरोह और अपहरणकर्ताओं की सक्रियता हो सकती है। इन अफवाहों के आधार पर ग्रामीणों ने एक निगरानी समूह का गठन किया। पीड़ितों में जूना अखाड़े के साधु चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरि (70 वर्ष) और सुशीलगिरि महाराज (35 वर्ष) और उनका 30 वर्षीय ड्राइवर नीलेश तेलगडे शामिल थे। वे सूरत में अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा कर रहे थे। इस दौरान पीड़ितों को गलती से बच्चा चोर और अंग काटने वाले समझ लिया गया।

ईगल कंपनी और बीएमसी लापरवाही के खिलाफ सपा ने निकला प्रचंड मोर्चा

मानखुर्द शिवाजीनगर में बंद पड़े आरसीसी रोड़ का कार्य, पेय जल (पानी) की समस्या से लोग परेशान...

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) मानखुर्द शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र में पिछले पांच महीनों से अधिकांश सड़के आरसीसी बनाने के लिए खुदी पड़ी है। जिसके कारण अवगामान भीतर की सड़कों पर पूरी तरह से ठप्प होने समेत बहुत सी रहीवासिय इलाकों में पेय जल समस्या की बढ़ती शिकायतों के कारण उजागर हुआ है।



वहीं मानखुर्द शिवाजी नगर के सपा विधायक अबू आसिम आजमी के निर्देश पर उनकी गैर मौजूदगी में आज सपा तालुका अध्यक्ष गैसुद्दीन शेख के नेतृत्व में सपा पूर्व आयशा नूरजहां रफीक शेख, नगरसेविका रुखसाना सिद्दीकी समेत बड़ी संख्या में चार वार्डों के पार्टी

पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एम पूर्व मनापा विभाग में कार्यरत लापरवाह अधिकारी, सीसी सड़कों का बनाने वाली ईगल कंपनी के विरोध में जमकर प्रचंड मोर्चा निकालकर नारे बाजी कर धेराव किया। सूत्रों के अनुसार सपा के प्रचंड मोर्चे की भनक लगते ही

एम पूर्व की सहायक आयुक्त अलका सासाने ने वार्ड से फरार हो गई। कहा जाता है की कोई भी कनिष्ठ अधिकारी आंदोलन करियों की विभिन्न मांगों का निवेदन लेने को तैयार नहीं हुए। पूर्व सपा नगरसेविका आयशा रफीक शेख ने कहा की जब से बीएमसी प्रशासक बनी तब से मनमाना कार भार करने में लगी है। हम लोग मनपा अधिकारियों को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे।

दूसरी ओर प्रभाग क्रमांक 136 की नगरसेविका रुखसाना सिद्दीकी ने कहा की बीएमसी अधिकारियों और ईगल कंपनी की मनमानी बंद नहीं हुई तो इससे भी बढ़कर सपा आंदोलन कर लिंक रोड़ की सड़क का चक्का जाम करेंगे।

महारेरा ने परियोजना की समय सीमा बढ़ा दी



मुंबई: महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) केवल घर खरीदार के हितों की रक्षा के लिए और डेवलपर पर कुछ शर्तों के साथ किसी भी आवास परियोजना की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति देता है। भले ही परियोजना की समय सीमा बढ़ा दी गई हो, घर खरीदार के अधिकार बरकरार रहेंगे। यदि किसी फ्लैट खरीदार को निर्धारित समय सीमा के अनुसार कब्जा नहीं मिलता है, तो वह नियमों के अनुसार महारेरा में जा सकता है। यदि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का कोई उल्लंघन होता है, तो आवास नियामक के पास जाना घर खरीदार का अधिकार है।

यदि कोई निश्चित आवास परियोजना एक वर्ष की विस्तारित समय सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो डेवलपर को घर खरीदारों से 51% सहमति प्राप्त करने के बाद ही एक और अतिरिक्त समय के लिए फाइल करने की अनुमति दी जाती है। यद्यपि घर खरीदार अपनी सहमति प्रदान करते हैं, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत उनके अधिकार कमजोर नहीं होते हैं। पीड़ित फ्लैट खरीदार पहले से दायर याचिका पर निष्पक्ष सुनवाई जारी रख सकता है या परियोजना/डेवलपर के खिलाफ महारेरा में जाने का इरादा रखता है।

कपड़ा बाजार के माथाडी कामगारों का आंदोलन शुरू... सरकार से घर निर्माण करके देने की मांग हुई तेज



मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) मुंबई के आजाद मैदान में पिछले कुछ दिनों से कपड़ा बाजार के माथाडी कामगारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर साकली

उपोषण शुरू किया है, कपड़ा बाजार माथाडी / हाथ गाड़ी चलाने वाले कामगार समाज के लोगों ने सरकार से मांग कि है कि सहयाद्री नगर, चारकोप कांदिवली मुंबई -67 में हमें शासन की ओर से दी गई सात एकड़ भूखंड पर कपड़ा बाजार के कामगारों के लिए घर बनाकर दी जाए। माथाडी कामगारों के विभिन्न मांगों को लेकर यूनिट ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निवेदन देकर आग्रह किया है कि सरकार अपने सभी घटक और राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करके हमारी मांगों को पूरी करें, अन्यथा हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा।

मुंबई में नसबंदी कराने में अब कम हिचकिचा रहे हैं पुरुष... 5 सालों में 159 परसेंट इजाफा

मुंबई: नसबंदी कराने को लेकर ज्यादातर पुरुष उपेक्षा का भाव रखते रहे हैं, लेकिन अब मुंबई में इसे लेकर एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। साल दर साल पुरुष नसबंदी के गिर रहे ग्राफ के बाद अचानक 2023 में पुरुषों की रुचि इसमें बढ़ी है। पिछले साल नसबंदी कराने वालों में 159

फीसदी का इजाफा हुआ है। वहीं, दूसरी तरफ महिलाओं में नसबंदी कराने की रुचि कम हुई है। उनमें 27 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। महिलाओं की नसबंदी से कम जटिल और जोखिम पुरुषों की नसबंदी में होती है। आमतौर पर जब भी परिवार नियोजन की बात आती है, तो



महिलाओं पर ही नसबंदी का दबाव पड़ता है। अब भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक संख्या में नसबंदी करवाती हैं। हालांकि वर्ष 2022-23 में पुरुषों की नसबंदी के आंकड़े में वृद्धि हुई है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 में 185 पुरुषों ने अपनी नसबंदी करवाई थी। इसके बाद साल दर साल आंकड़ा गिरता चला गया। 2019-20 में 116, 2020-21 में 49, 2021-22 में 58 लोगों ने

नसबंदी करवाई, लेकिन 2022-23 में 480 पुरुष नसबंदी करवाई है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पुरुषों को लगता है कि उनके नसबंदी कराने से उनके सेक्सुअल जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा। यह सबसे बड़ा भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमारे डॉक्टरों, सीएचवी दंपती को समझाते हैं। पुरुषों को इंसेंटीव्स तो देते ही हैं। उनकी दुविधाओं का भी निवारण

करते हैं। इसी के सरकार उन्हें लगभग 1,420 रुपये इंसेंटीव भी देती है।

पुरुष की नसबंदी करने मात्र 30 मिनट का समय लगता है और जोखिम भी कम होता है, जबकि महिलाओं की ओपन सर्जरी होती है और जान जाने का भी खतरा होता है। मुंबई में बीएमसी के 28 प्रसूति गृह, 17 उपनगरीय अस्पताल और 4 मेडिकल कॉलेज निशुल्क नसबंदी की जाती है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के एफ साउथ वार्ड में एक समर्पित नसबंदी प्रशिक्षण और ऑपरेशन थिएटर है। यदि कोई पुरुष नसबंदी सर्जरी के लिए आता है, तो उसी दिन पूछताछ, परीक्षण आदि कर सर्जरी कर दी जाती है।

आईएमए भी कर रहा है नसबंदी

बीएमसी स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पुरुषों में नसबंदी का ग्राफ बढ़ने में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी सहायता कर रहा है। डॉक्टरों को रिप्रेजेंट करनेवाले संगठन आईएमए ने पहल कर वहीं में नसबंदी का एक केंद्र खोला है। सरकारी इंसेंटीव्स के अलावा आईएमए नसबंदी कराने वाले पुरुषों को लगभग 10,000 रुपये देता है। यानी बीएमसी के साथ आईएमए परिवार नियोजन में मदद कर रहा है।

पुरुष नसबंदी तीन महीने के बाद सफल होती है।

महिला नसबंदी का गिरता ग्राफ

पिछले 5 वर्षों में महिलाओं की नसबंदी में लगभग 27 की गिरावट दर्ज की गई है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में 19263 महिलाओं ने नसबंदी की सर्जरी करवाई थी। वहीं 2022-23 में 14029 महिलाओं ने नसबंदी के लिए सर्जरी करवाई। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आजकल लोग नसबंदी के लिए स्थायी उपाय के बजाय टेपेरी सांल्यूशन अपना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग कंडोम और ओरल कंटेसेप्टिव पिल्स का उपयोग कर सर्जरी से बच रहे हैं। हम यह भी पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने लोग टेपेरी सांल्यूशन को अपना रहे हैं।

भाजपा को नहीं समझ पाए राउत - चंद्रकांत पाटिल

लोकसभा चुनाव में महायुति के पदाधिकारियों का किया मार्गदर्शन

मुंबई : आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, जिसे पूरा करने के लिए भाजपा एक-एक नेता और कार्यकर्ता काम पर लग गया है। इसी कड़ी में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सोमवार पुणे में पुणे, बारामती और शिरूर लोकसभा क्षेत्र के महायुति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पाटिल ने इस महत्वपूर्ण बैठक में महायुति के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया और चुनाव की तैयारी में लग जाने का निर्देश दिया। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव में एनडीए के 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है जिसे हमें पूरा करने के लिए चुनाव की तैयारी में लग जाना पड़ेगा। पाटिल ने यूबीटी के सांसद संजय राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि वह भाजपा को



नहीं जानते। चार दिन पहले भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई जो सुबह साढ़े तीन बजे तक चली। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बैठक में उपस्थित थे वे बैठक खत्म होने के बाद सुबह साढ़े तीन बजे घर गए और सुबह आठ बजे पांच देशों के दौरे पर निकल गए, क्या संजय राउत को है ये आदत है ? पाटिल ने कहा कि राउत को बाहर जाने की आदत डालनी और

काम पर ध्यान देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राउत को लापरवाही नहीं बल्कि अपना काम ठीक से करनी चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पिछली एमवीए की सरकार में जनता से मंत्री, सांसद, विधायक नहीं मिल रहे थे। यदि आप हमसे मिलने नहीं मिलेंगे तो जनता का काम कैसे होगा। उद्धव ठाकरे का बिना नाम लिए पाटिल ने कहा कि जब मुख्यमंत्री थे तब किसी से नहीं मिलते थे अब जब शिवसेना में भारी फूट पड़ गई है तो वे लगातार दौरा कर रहे हैं। लेकिन इसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नहीं की जा सकती। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जो सहकर्मी वर्षों से उनके साथ थे, उन्हें वे अपने साथ नहीं रख पाए उन्हें पता ही नहीं चला कि यह कब उनकी नाक के नीचे से उनका साथ छोड़कर चले गए।

मुंबई की 2 बहनों का यह गैंग पहले करता प्यार, शादी का वादा; फिर टगी !

मुंबई: आरे पुलिस के तहत एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें दो युवतियां अपने माता-पिता की मदद से युवाओं को अपने प्यार में फांसी थीं और फिर शादी करने का झांसा देकर टगी की घटना को अंजाम देती थीं। इस परिवार के खिलाफ करीब आधा दर्जन लोगों ने आर्थिक रूप से



टगी करने का आरोप लगाया है। आरे पुलिस ने एक युवक से करीब 13 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी

पुलिस से नहीं मिला सहयोग... कोर्ट की शरण

परेशान होकर जब वह आरे पुलिस पहुंचा, तो पुलिस से सहयोग नहीं मिला। इसके बाद उसने सभी सबूतों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर आरे पुलिस ने हरप्रीत, उसकी बहन मनप्रीत, सास मनीषा रामगडिया और ससुर बलविंदर रामगडिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगडिया परिवार के खिलाफ युवक द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

शादी के बाद रंग बदलने लगी...

पीड़ित युवक के मुताबिक, शादी के कुछ दिन बाद हरप्रीत और उसके परिवार वाले उससे कभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने, तो कभी शादी के बाद घर खरीदने के नाम पर उससे पैसे मांगने लगे। आरोप है कि हरप्रीत और उसके मां-बाप केश, जूलरी और कर्ज के बहाने उससे भारी रकम लेते रहे। हरप्रीत की मां ने उससे अपनी बेटी के लिए एक करोड़ रुपये कीमत का एक प्लैट मुंबई में खरीदने का भी दबाव डाला। चूंकि, भारी भरकम कर्ज लेकर प्लैट खरीदना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए महंगे प्लैट खरीदने से उसने मना कर दिया। इसके बाद हरप्रीत और उसके माता-पिता उससे दूरी बनाने लगे। हरप्रीत के साथ रहने से मना कर दिया।

पाइपलाइन लीकेज और मरम्मत के तमाम बहाने बनाकर हो रही पानी कटौती, किल्लत से जूझ रहे मुंबई के लोग

मुंबई: बीएमसी ने कई साल पहले मुंबईकरों को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन उसका यह दावा फेल हो गया। हालत यह हो गई है कि मुंबईकरों को मार्च महीने से ही पानी कटौती का सामना करना पड़ रहा है। झीलों में जलस्तर कम होने पर पहले जुलाई या अगस्त में पानी कटौती का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस साल स्थिति बदतर दिखाई दे रही है। पिसे

वॉटर पंपिंग स्टेशन में आग लगने के कारण मुंबईकर 27 फरवरी से ही 15-30 प्रतिशत तक की पानी कटौती का सामना कर रहे हैं। कभी किसी इलाके में पाइपलाइन में लीकेज हो रही है तो कभी नई पाइपलाइन बिछाने के नाम पर पानी की कटौती की जा रही है। कभी पाइपलाइन फूट जाती है, तो कहीं वॉल्व बदलने के नाम पर मुंबई के किसी न किसी इलाके में पानी कटौती का सामना करना पड़ता है।



सरकार ने लिया राहत देने वाला फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी की मांग को स्वीकार करते हुए मुंबई को रिजर्व वायर से अतिरिक्त 10 प्रतिशत

पानी देने पर सहमत जता दी है। सरकार ने भातसा और अपर वैतरणा से बीएमसी को पानी उपलब्ध कराने की बात कही है। सरकार के इस कदम से मुंबईकरों पर 1 मार्च से 30 जून तक 10 प्रतिशत तक की पानी कटौती का जो संकट मंडरा रहा था, वह फिलहाल टल गया है। राज्य सरकार ने बीएमसी को अतिरिक्त पानी मुहैया नहीं कराया होता, तो अगले चार महीने तक लोगों को पानी किल्लत

का सामना करना पड़ता।
50 से 100 साल पुरानी है पाइपलाइन
मुंबई में पाइपलाइन लीकेज और चोरी की वजह से करीब 25 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है। इस कड़वी सच्चाई को बीएमसी भी जानती है। मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली ज्यादातर पाइपलाइन 50 से 100 साल पुरानी हैं। ऐसे में जगह-जगह लीकेज की घटनाएं बढ़ रही हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को किया बरी

महाराष्ट्र : बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) ने मंगलवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. को बरी कर दिया। साईबाबा और पांच अन्य को 2014 माओवादी लिंक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मिकी एस.ए. मेनेजस की खंडपीठ ने गढ़चिरोली सत्र न्यायालय के 2017 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने पहले छह आरोपियों को दोषी ठहराया था। राज्य ने 5 मार्च, 2017 को दिए गए फैसले पर रोक लगाने की मांग नहीं की, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की पिछली पीठ द्वारा अक्टूबर 2022 में प्रोफेसर को बरी करने के बाद साईबाबा की याचिका पर दोबारा सुनवाई के बाद आया था। 2014 में गिरफ्तार, 54 वर्षीय साईबाबा, जो मानसिक रूप से स्वस्थ और सतर्क हैं, व्हीलचेयर पर बंधे रहते हैं और वर्तमान में नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। अन्य आरोपियों - महेश तिकी, विजयनान तिकी, हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही और पांडु पोरा नरोटे



(जिनकी अगस्त 2022 में मृत्यु हो गई) के साथ गिरफ्तारी के बाद उन पर क्षेत्र में सक्रिय माओवादी संगठनों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया गया। और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे हैं। न्यायाधीशों ने मंगलवार को आरोपियों को 50,000 रुपये जमानत बांड के रूप में जमा करने के बाद जेल से रिहा करने का निर्देश दिया, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ राज्य की याचिका पर फैसला नहीं करता, अगर इसे चुनौती दी जाती है। मामले की मौजूदा दोबारा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर 2022 के बरी करने के आदेश को रद्द करने और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए

बॉम्बे हाई कोर्ट में भेजने के बाद हुई गढ़चिरोली सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे में, महाराष्ट्र राज्य ने तर्क दिया कि वह और अन्य लोग प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) समूह और रिजोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसे उसके प्रमुख संगठनों के लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने साईबाबा के पास से माओवादी साहित्य, पर्चे, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और 'राष्ट्र-विरोधी' समझी जाने वाली अन्य चीजें जैसे सबूत जब्त किए थे। उन्होंने कथित तौर पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर 4,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अबुझमाड़ के जंगलों में सक्रिय और छिपे माओवादी समूहों के लिए 16 जीबी का मेमोरी कार्ड भी सौंपा था। मार्च 2017 में गढ़चिरोली सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद, साईबाबा ने बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) और न्यायमूर्ति रोहित बी देव और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ में फैसले को चुनौती दी थी।

मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय स्तर पर गाडीया चोरी करनेवाले गिरोह बेनकाब...



मीरा भाईंदर : मीरा भाईंदर सेंट्रल युनिट की क्राइम ब्रांच सेल नंबर १ ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कंपनियों के ट्रक, आयशर टेम्पो और अन्य वाहनों को चुराता था और उन्हें फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच देता था। मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ने जानकारी दी है कि 47 वाहन जिनकी कीमत ७,३२,४१,००० बतायी जा रही है। इस मामले में ४ अपराधी पुलिस के

हाथ चढ़े हैं और भी आरोपी इस गिरोह में होने की आशंका पुलिस ने जतायी है। राष्ट्रीय स्तर पर वाहन चोरी करने वाले गिरोह हुए हैं। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ४७ वाहनों को जब्त किया गया है। ये चोरी करने वाले विभिन्न कंपनियों के ट्रक, टेम्पो और अन्य वाहनों को चोरी करके उनके विक्रेताओं को बनावटी कागजात और कागदपत्रों के साथ बेचते थे। पिछले गाडी चोरी के मामले को देखते मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे द्वारा क्राइम युनिट १ को यह काम सौंपा था। इस युनिट के अधिकारी प्रशांत गांगुर्डे को जांच में एक आरोपी का पता चला और उसके पास से और आरोपीयो का मालूमत मिळते उन्हे दबोचा गया। जांच के दौरान आरोपियों ने सबसे पहले झूठे दस्तावेजों के आधार पर ट्रेनों को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि राज्यों में भेजा, जबकि वे अस्तित्व में ही नहीं थे। राज्यों में विभिन्न आरटीओ कार्यालय में कारों का पंजीकरण कराने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर व अन्य दस्तावेज प्राप्त कर लिए गए। संबंधित आरटीओ ने कहा कि उन दस्तावेजों के आधार पर, उक्त वाहनों को महाराष्ट्र राज्य में फिर से पंजीकृत किया जाना है। कार्यालय ऑनलाइन एनओसी प्राप्त फिर दस्तावेजों पर उल्लिखित मेक और मॉडल के साथ विभिन्न राज्यों से कारें चुराई गई।

सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों ने किया रुख...

स्पीकर के फैसले को दी चुनौती



हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान व्हिप का उल्लंघन करने पर स्पीकर ने छह कांग्रेस विधायकों को अयोग्य करार दिया है। अब इन 6 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन कांग्रेसी विधायकों ने स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती दी है। स्पीकर ने विधानसभा में बजट के दौरान अनुपस्थित रहने के आधार पर इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को गलत ठहराते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि

ठाकुर, देवेन्द्र भुट्टे और चैतन्य शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने इन सभी 6 कांग्रेस विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है। विधानसभा स्पीकर ने यह फैसला बतौर ट्रिब्यूनल चैयरमैन सुनाया है। दल बदल कानून के तहत सदस्यता गंवाने वाले इन विधायकों ने खुद को अयोग्य करार दिए जाने वाले फैसले को चुनौती दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हिप हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को एक शिकायत सौंपी थी। इस शिकायत में इन सभी 6 विधायकों के व्हिप जारी होने के बावजूद कटौती प्रस्ताव और बजट पारण के दौरान अनुपस्थित रहने की बात कही गई।

मुंबई में डिवाइडर पर चढ़ी बेस्ट की बस... कोई हताहत नहीं

मुंबई : बेस्ट की बस रविवार की रात 1 बजे के दरम्यान एक दूसरे वाहन से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना रात 1 बजे घटने के कारण बस में यात्रियों की संख्या तो कम थी ही सड़क पर लोगों का आवागमन नहीं था, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। मिली जानकारी के अनुसार बेस्ट की बस जो कि बांद्रा डिपो से सीबीडी बेलापुर जा रही थी।



थी उससे टकरा कर डिवाइडर पर चढ़ गई। बस वासी के आगे पामबीच पर तेज रफ्तार से जा रही थी, उस समय यह घटना घटी। बेस्ट की बस जिस समय डिवाइडर पर चढ़ी उस समय कुछ लोग सड़क पार करने के

लिए खड़े हुए थे। अनियंत्रित बेस्ट बस को अपनी ओर आते देख लोगों ने अपने जान बचाकर भागे। दुर्घटना के समय बेस्ट बस में मात्र 3 से 4 यात्री सवार थे, जिन्हें बेस्ट बस के दुर्घटना होने पर झटका लगने से मामूली चोट लगी। बेस्ट प्रशासन ने बस दुर्घटना की जानकारी देते हुए कहा कि बस में सवार यात्रियों को मामूली चोट लगी है, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं है कि ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़े। बस ड्राइवर अथवा कंडक्टर को चोट नहीं लगी है बस को बड़ा नुकसान हुआ है।

बदलते तापमान और प्रदूषण के कारण बढ़ रही श्वसन संबंधी समस्याएं

मुंबई : लगातार खांसी, सर्दी और गंभीर गले में खराश से पीड़ित मरीजों की संख्या पिछले दो हफ्तों में काफी बढ़ गई है। डॉक्टरों के मुताबिक, चिंताजनक उछाल के लिए दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव जिम्मेदार है। हालांकि, कुछ चिकित्सकों ने ऐसी बीमारियों में वृद्धि को लगातार खराब वायु गुणवत्ता से भी जोड़ा है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक मुंबई में ठंडी हवाएं और कम तापमान रहेगा। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, आइए लालबाग इलाके के निवासी 17 वर्षीय समीर चव्हाण का मामला लें। हालांकि उन्हें कोई अंतर्निहित सह-रुग्णता नहीं थी, फरवरी के मध्य में उन्हें खांसी हुई, जो धीरे-धीरे बढ़कर सर्दी



में बदल गई। कई दौर की एंटीबायोटिक दवाओं और कुछ छाती के एक्स-रे के बाद, उन्हें ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण का पता चला। पिछले दो महीनों में, डॉक्टरों ने चव्हाण जैसे रोगियों में वृद्धि देखी है, जो वायरल बीमारी से पूरी तरह ठीक होने के बाद भी लगातार खांसी से पीड़ित

हैं। इन मरीजों पर अक्सर सामान्य खांसी की दवा का असर नहीं होता है और उन्हें इन्हेल स्टेरॉयड की आवश्यकता होती है। डॉक्टरों के अनुसार, हाल ही में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के बा' रोगी विभाग (ओपीडी) में आने वाले लगभग 40-50% रोगियों ने ऊपरी श्वसन खांसी, सर्दी और चक्कर आने की शिकायत की। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसके लिए न केवल मौसम के उतार-चढ़ाव को जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि प्रदूषण और धुंध भरी हवा में सांस लेने के कारण लंबे समय तक सांस संबंधी समस्याओं से जूझना भी बताया है। उन्होंने ऐसी बीमारियों के पीछे स्वास्थ्य के प्रति लोगों की लापरवाही को भी एक कारण के रूप में रेखांकित किया।

सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य से अयोग्य घोषित हो चुके इन विधायकों का कहना है कि स्पीकर ने इन्हें अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया। इसके अलावा नोटिस भी सिर्फ एक ही विधायक को मिला, अन्य विधायकों को नोटिस भी नहीं दिया गया। विधायकों के वकील ने यह भी कहा कि स्पीकर ने इस तरह फैसला लिया कि मानो पिटीशन में लिखी गई हर बात सत्य हो। अब सुप्रीम कोर्ट से इन विधायकों को राहत की उम्मीद है। अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो इन सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokhoklekhaninews.com